भारत सरकार
शिक्षा मंत्रालय
स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या-1208
उत्तर देने की तारीख-27/07/2026

विद्यालयों में दी जाने वाली शिक्षा की गुणवत्ता का आकलन

†1208. **श्री जनार्दन सिंह सीग्रीवाल:**
क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:
(क) क्या सरकार ने देश के विद्यालयों और उच्च शिक्षण संस्थानों में दी जाने वाली शिक्षा की गुणवत्ता का हाल ही में कोई मूल्यांकन किया है;
(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी राज्य वार/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है, साथ ही सरकारी और गैर-सरकारी संस्थानों में अधिगम परिणामों, शिक्षकों की गुणवत्ता और अवसंरचना के बारे में मुख्य निष्कर्ष क्या हैं;
(ग) क्या सरकार ने आधारभूत साक्षरता और संख्या-ज्ञान, डिजिटल अधिगम और शिक्षक प्रशिक्षण में शिक्षा की गुणवत्ता पर प्रभाव डालने वाली कोई कमी पाई है;
(घ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, साथ ही शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने के लिए विभिन्न योजनाओं और कार्यक्रमों के अंतर्गत किए गए या किए जाने वाले सुधारात्मक उपायों का ब्यौरा क्या है; और
(ङ) क्या सरकार ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के उद्देश्यों के अनुसार शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिए कोई मापनीय लक्ष्य और समय-सीमा नियत की है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री जयन्त चौधरी)

(क) से (ङ): शिक्षा संविधान की समवर्ती सूची के अंतर्गत आती है, जिसमें अधिकांश स्कूल और उच्चतर शिक्षा संस्थान (एचईआई) राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के दायरे में आते हैं। अपनी ओर से, शिक्षा मंत्रालय राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के मार्गदर्शन में कार्य करता है, जो शिक्षार्थियों के समग्र विकास तथा मूल्यांकन की ऐसी पद्धतियों पर बल देती है, जिसमें रटने पर आधारित और केवल अंतिम परीक्षाओं के स्थान पर नियमित, निर्माणात्मक और योग्यता-आधारित मूल्यांकन को अपनाया जाता है जो अधिगम, आलोचनात्मक चिंतन, वैचारिक समझ तथा शिक्षण-अधिगम प्रक्रियाओं में निरंतर सुधार को बढ़ावा देती है।

एनईपी 2020 की सिफारिशों के अनुसरण में, शिक्षा मंत्रालय द्वारा दिनांक 8 फरवरी, 2023 को राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र, परख (समग्र विकास के लिए ज्ञान का प्रदर्शन मूल्यांकन, समीक्षा और विश्लेषण) की स्थापना की गई थी। परख स्कूलों में विद्यार्थी मूल्यांकन और आकलन हेतु मानदंड, मानक और दिशानिर्देश निर्धारित करता है तथा समय-समय पर आयोजित परख राष्ट्रीय सर्वेक्षण (पूर्व में राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण) जैसे बड़े पैमाने के मूल्यांकन के माध्यम से स्कूल शिक्षा प्रणाली की गुणवत्ता एवं स्थिति की निगरानी करता है।

एनईपी 2020 के तहत, परख राष्ट्रीय सर्वेक्षण (पीआरएस) 2024 का आयोजन शिक्षा के मूलभूत, प्रारंभिक और मध्य चरणों अर्थात कक्षा 3, 6 और 9 के अंत में छात्रों में दक्षताओं के विकास में आधारभूत प्रदर्शन को मापने के लिए दिसंबर 2024 में किया गया था। यह

सर्वेक्षण स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार हेतु साक्ष्य-आधारित मध्यवर्तनों को सहयोग प्रदान करने के लिए अधिगम परिणामों और प्रासंगिक कारकों पर जिला-स्तरीय साक्ष्य प्रदान करता है।

सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के 781 जिलों के 74,000 से अधिक स्कूलों के 21.15 लाख से अधिक विद्यार्थियों और 2.70 लाख शिक्षकों तथा स्कूल प्रमुखों ने सर्वेक्षण में भाग लिया, जिससे यह देश में आयोजित विद्यार्थी अधिगम के सबसे व्यापक मूल्यांकनों में से एक बन गया। परख राष्ट्रीय सर्वेक्षण 2024 के निष्कर्षों से स्पष्ट होता है कि एनएएस 2021 की तुलना में मूलभूत साक्षरता एवं संख्याज्ञान (एफएलएन) कौशलों में उल्लेखनीय सुधार हुआ है, जो एनईपी 2020 के अंतर्गत प्रारंभ किए गए निपुण भारत मिशन के सकारात्मक प्रभाव को दर्शाता है।

अधिगम प्रदर्शन को प्रभावित करने वाले संभावित कारकों की पहचान करने तथा अधिगम परिणामों में सुधार हेतु साक्ष्य-आधारित मध्यवर्तनों को सक्षम बनाने के उद्देश्य से परख राष्ट्रीय सर्वेक्षण के दौरान शिक्षक प्रशिक्षण, शैक्षणिक दृष्टिकोण एवं प्रयुक्त शिक्षण-अधिगम सामग्री, घरेलू परिवेश एवं संसाधनों, डिजिटल पहुँच एवं उपयोग, स्कूली सहयोग, स्कूली अवसंरचना एवं समावेशिता तथा सामुदायिक सहभागिता आदि से संबंधित संदर्भगत आँकड़े भी एकत्र किए गए। परख राष्ट्रीय सर्वेक्षण 2024 के लिए राष्ट्र, राज्य और ज़िला स्तरीय रिपोर्ट https://dashboard.parakh.ncert.gov.in/en पर उपलब्ध हैं जो मूल्यांकन के निष्कर्षों को प्रसारित करने के लिए तैयार किया गया एक विशिष्ट डैशबोर्ड है।

उच्चतर शिक्षा के संबंध में, राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद (एनएएसी) उच्चतर शिक्षण संस्थानों (एचईआई) का उनकी गुणवत्ता संबंधी गतिविधियों के आधार पर मूल्यांकन एवं प्रत्यायन करता है तथा उनकी उपलब्धियों के लिए उन्हें ग्रेड प्रदान करता है। इसके अतिरिक्त, भारत सरकार द्वारा वर्ष 2015 में शुरू किए गए राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क (एनआईआरएफ) ने "शिक्षण, अधिगम और संसाधन", "अनुसंधान और व्यावसायिक पद्धति", "स्नातक परिणाम", "पहुंच और समावेशिता" तथा "सहकर्मी धारणा" जैसे प्रमुख मापदंडों के आधार पर एचईआई की रैंकिग की है। रैंकिंग प्रत्येक वर्ष घोषित की जाती है और एनआईआरएफ वेबसाइट पर प्रकाशित की जाती है, जो सभी हितधारकों के साथ-साथ आम जनता के लिए भी उपलब्ध है।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) 2020 इसके कार्यान्वयन के लिए अलग-अलग समयसीमा, सिद्धांत और कार्यप्रणाली प्रदान करती है। विभिन्न योजनाओं के तहत विविध मध्यवर्तनों का उद्देश्य शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करना है। समग्र शिक्षा की केंद्र प्रायोजित योजना शिक्षकों और स्कूल प्रमुखों के सेवाकालीन प्रशिक्षण, अनुकूल शिक्षण परिवेश प्रदान करने के लिए प्रत्येक स्कूल को कम्पोजिट स्कूल अनुदान, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों (सीडब्ल्यूएसएन) हेतु सहायता, पुस्तकालय, खेल और शारीरिक गतिविधियों हेतु अनुदान, राष्ट्रीय अविष्कार अभियान, टिंकरिंग लैब्स, आईसीटी एवं डिजिटल पहलों हेतु सहायता, स्कूल नेतृत्व विकास कार्यक्रम, शैक्षणिक रूप से कमजोर छात्रों के लिए सुधारात्मक शिक्षण, नई शैक्षणिक और पाठ्यचर्या संरचना की शुरूआत, निपुण भारत पहल, ईसीसीई सुविधाओं सहित बाल-अनुकूल एवं समावेशी कक्षाएँ, स्कूल प्रबंधन समितियों (एसएमसी) का सुदृढ़ीकरण एवं समुदाय-आधारित पहलें, आवासीय विद्यालयों/छात्रावासों को खोलना, सुदृढ़ीकरण/स्तरोन्नयन, पात्र बच्चों को निःशुल्क यूनिफॉर्म एवं प्रारंभिक स्तर पर निःशुल्क पाठ्यपुस्तकें, परिवहन भत्ता प्रदान करना तथा नामांकन एवं प्रतिधारण को बढ़ावा देने के लिए अभियान चलाना जैसे विभिन्न मध्यवर्तनों हेतु सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को सहायता प्रदान करके शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार पर केंद्रित है। इसके अतिरिक्त, प्रधान मंत्री पोषण शक्ति निर्माण (पीएम पोषण) की केंद्र प्रायोजित योजना के तहत, सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में प्रारंभिक स्तर (बालवाटिका सहित) के विद्यार्थियों को उनकी पोषण संबंधी आवश्यकताओं का ध्यान रखने और उनकी उपस्थिति में सुधार हेतु दिन में एक बार पका हुआ गर्म भोजन प्रदान किया जाता है। प्रधानमंत्री स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया

(पीएम श्री) की केंद्र प्रायोजित योजना के तहत, एनईपी 2020 के सभी पहलुओं को प्रदर्शित करने और अनुकरणीय स्कूलों के रूप में कार्य करने के लिए मौजूदा स्कूलों को सुदृढ़ किया जा रहा है। इसका उद्देश्य रटने पर आधारित शिक्षा के स्थान पर समग्र, अनुभवात्मक एवं दक्षता-आधारित अधिगम के माध्यम से मूलभूत साक्षरता एवं संख्याज्ञान पर बल देना, अवसंरचनात्मक उन्नयन करना, पर्यावरणीय चिंताओं के प्रति संवेदनशीलता विकसित करना तथा आलोचनात्मक चिंतन एवं 21वीं सदी के अन्य कौशलों का विकास करते हुए शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करना है।

*****